in costs of operations and production and strive to become more competitive both in domestic and international markets. This would apply uniformly to all the steel plants in the Public Sector including SAIL.

(c) and (d) While at present there is no proposal for privatisation of any of the SAIL steel plants, this is only one aspect of the Government's liberalisation policy. SAIL have taken due note of other features of the new economic policy of the Government the effect of which would only be known over a period of time.

टिस्को द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

1766. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा समूह अपने लोहे और इस्पात के प्राइम उत्पादन के 12 प्रतिशत भाग को "टिस्को रिजेक्टिड" चिन्हित करके उसे अपनी एजेंसियों के माध्यम से बेच कर प्राइम इस्पात की कीमत वसूल करता है और इस प्रकार वह उत्पाद शुल्क का अपवंचन करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार रेंज के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी तथा जमशेदपुर में तैनात उत्पाद शुल्क अधिकारी टाटा समूह के साथ सांठगांठ कर के उत्पाद शुल्क का बड़े पैमाने पर घोटाला करता है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी संसदीय समिति से कराने और प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि को रोकने का विचार रखती है, और क्या सरकार जमशेदपुर और रांची स्थित उत्पाद शुल्क अधिकारियों के आवासों पर छापे मारने का विचार भी रखती है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देब) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स खेतान को मिक्स्ड कोक की बिक्री

1767. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक अपना कार्यभार सौंपने से कुछ दिन पूर्व समस्त प्रक्रियाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य का 1.85 लाख टन मिक्स्ड कोक मैसर्स खेतान को बेच दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इतनी बडी मात्रा में कोक बेचने का सौदा बिक्री संबंधी किसी प्रक्रिया का पालन न करके केवल धन के लेन देन के आधार पर तय किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रबंध निदेशक और स्टील अथारिटी आफ इंडिया के वर्तमान वाणिज्य निदेशक ने बंगलोर में एक बहुत बड़ी सात मंजिली इमारत का निर्माण कराया है , जिसकी लागत उनके ज्ञात आय स्त्रोतों से बहुत ज्यादा है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर "हां" हो तो सरकार इन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ; क्या उन्हें उनके वर्तमान पद से मुक्त कर दिया जाएगा और बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंध निदेशक के रूप में उनके क्रियाकलापों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाएगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देब) : (क) और (ख) एकमत प्रस्ताव और एकमात्र मध्यस्थ पंचाट के आधार पर बोकारो इस्पात संयंत्र के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने 28 मार्च, 1990 को संशोधित बिक्री आर्डर को स्वीकृत किया था ताकि मैसर्स स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड 13,97,22, 400/- रु० मूल्य का 1,74,653 टन मिश्रित

कोयला उठा सके । उपर्युक्त निर्णय प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप था और इससे प्रचलित कार्य प्रणाली का उल्लंघन नहीं हुआ ।

(ग) "सेल" के रिकार्ड और अधिकारी के सम्पत्ति विवरण के अनुसार इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जाना

1768. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ; और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पत्रकारों के लिए नया वेतन आयोग प्रति पांच वर्ष के बाद नियुक्त किया जाता है, क्या सरकार उनके लिए एक ऐसा आयोग नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार विभिन्न स्तरों पर बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों पर कार्यान्वयन पर नजर रखने और इसके लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालती रही है इस बारे में केंद्रीय श्रम मंत्री ने भी दिसम्बर, 1989 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था । बछावत बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मासिक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राप्त हो रही है ।

(ग) जी नहीं ।

Durgapur steel plant

1769. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the progress of the modernisation of Durgapur Steel Plant has not been achieved as per schedule and as a result of which there has been sharp cost increase;

(b) whether the performance of Birla Technical Services has been very poor in handling such gigantic steel plant; if so, the details thereof;

(c) whether the DSP has made huge payments to BTS and Mannesmann Demag of West Germany during the last three years;

(d) if so, the details thereof; and

(e) what was the initial schedule of completion and the present position of the total project of modernisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI SANTOSH MOHAN DEB): (a) Though the progress of execution of certain packages of work in the project for modernisation of Durgapur Steel Plant has not been in accordance with the schedules drawn, the overall completion schedule of March, 1993 set for the whole project is likely to be adhered to. There has not been any increase in the cost of the project beyond the sanctioned costs.

(b) There have been certain slippages in respect of certain responsibilities and scope of work assigned to M/s. Birla Technical Services. However, SAIL find the performance for their scope of work in the project satisfactory on the overall basis so far.